30/04/2020
Thursday

स्तुतीय हैं।

गोपालकृष्ण गोखले का प्रस्ताव 1910

बड़ौदा नरेश के प्रारम्भिक प्रयासों से राष्ट्रवादी नेताओं का मनोबल अत्याधिक बढ़ गया। किन्तु सरकार ने इस दिशा में कोई रुचि नहीं ली। इस स्थिति से जुझने का कठोर प्रयास 'गोपाल कृष्ण गोखले' किया। वे इस समय 'केन्द्रीय धारा सभा' के सदस्य थे।

गोखले ने 19 मार्च 1910 को केन्द्रीय सभा में अपना विस्फोटक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा – "यह सभा सिफारिश करती है, कि सम्पूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा निः शुल्क एवं अनिवार्य बनाने

Scanned with CamScanner

का कार्य प्रारम्भ किया जाए। इस शिक्षा के विभिन्न प्रश्नों का विवेचन करने के लिए "सरकारी और गैर सरकारी अधिकारियों" की एक संयुक्त आयोग शीघ्र ही नियुक्त किया जाए।

प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव के मुख्य बिन्दु

1-> प्राथमिक शिक्षा की देखरेख के लिए एक प्रथक मन्त्री परिषद की नियुक्ति।
2-> पृथक विभाग की स्थापना की जाए,
3-> अनिवार्य एवं निःशुल्क (प्राथमिक शिक्षा) को बनाने के लिए आवश्यक व्यय स्थानीय संस्थाओं और सरकार के मध्य 1:2 की साझेदारी।
4-> पिछड़े क्षेत्रों में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा लागू की जाए।

गोखले का प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी विधेयक 1911 ->

ब्रिटिश सरकार के खोखले आश्वासन से क्षुब्ध गोखले ने 16 मार्च 1911 को केन्द्रीय सभा के समक्ष प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी अपना विधेयक bill प्रस्तुत किया।

इसमें निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी।

-> अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम केवल उन स्थानीय बोर्डों के क्षेत्रों में लागू किया जाय. जहाँ बालक/बालिकाओं का एक निश्चित प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करता हो।
-> इस अधिनियम को लागू करने से पूर्व सरकार की अनुमति लीजाय।
-> 6-10 वर्ष की आयु के सभी बालक/बालिकायें विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए बाध्य।
-> जिन अभिभावकों की आयु 100 से कम है, निःशुल्क शिक्षा।
-> बालिकाओं की शिक्षा अनिवार्य।

'17 मार्च सन् 1912' को केन्द्रीय सभा में तीक्ष्ण वाद-विवाद हुआ इस विधेयक को 'हार का सामना' करना पड़ा।
सरकारी प्रवक्ता 'सर हार्टकोर्ट बटलर' ने गोखले के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत किये ->

① इसके लिए 'प्रान्तीय सरकारें' मानसिक रूप से तैयार नहीं।
② शिक्षित वर्गों द्वारा विरोध करना।

Scanned with CamScanner

→ शब्द अनिवार्य शिक्षा के तैयार नहीं।
→ जन साधारण भी प्राथमिक शिक्षा के प्रति आकृष्ट नहीं।
→ अनेक गम्भीर प्रशासनीय कठिनाईयाँ उपस्थित।

प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव 1913

लार्ड कर्जन शिक्षा शब्द विरोधी नीति।
राष्ट्रीय नेतृत्व में शैक्षिक चेतना।
गोपाल कृष्ण गोखले के विधेयक को सरकार द्वारा अमान्य घोषित।
अंग्रेज सम्राट जार्ज पंचम का भारत यात्रा के समय दिया गया भाषण।
आदि कारणों से ब्रिटिश सरकार को प्राथमिक शिक्षा के लिए बाध्य होना पड़ा। इसे सरकार ने एक 'दस्तावेज' के रूप में प्रस्तुत / प्रकाशित किया :-

→ अधिका धिक प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना।
→ उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकतानुसार स्थापना।
→ निजी विद्यालयों में व्यवस्थित निरीक्षण का प्रबन्ध।
→ विद्यालयों में क्षेत्रीय शिक्षकों की नियुक्ति।
→ ग्रीष्मकालीन शिविरों में शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

प्राथमिक शिक्षा के अतिरिक्त 'दो अन्य संस्थान' भी प्रकाशित किये गये। इनमें सन् '1780 में कलकत्ता मदरसा' खुला तथा सन् '1791 में बनारस रेजीडेन्ट जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज' को प्रारम्भ किया।

B.R.C. Deoband
Assis Pro — Sapna Tyagi

Scanned with CamScanner